राष्ट्रीयकृत बैंकों के शीर्ष पदों पर नियुक्तियां

3504. **श्री शिव प्रताप मिश्र :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 फरवरी, 1993 के इंडियन एक्सप्रेस (नई दिल्ली) में "फाइनेन्स मिनिस्ट्री, सी० बी० आई० पुल्ड अप पी० एम० ब्लाक्स टेन्टेड बैंकर्स प्रोमोशन" शीर्षक से छपे समाचार की ओर गया है जिसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में शीर्ष पदों की नियुक्तियों के लिए संदिग्ध चरित्र वाले व्यक्तियों के नामों की स्वीकृति के संबंध में प्रधान मंत्री ने प्रतिकूल टिप्पणियां की हैं,

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं और उन्हें किन-किन बैंकों में नियुक्त किया जाना था, और

(ग) किन कारणों से उन व्यक्तियों की सिफारिश की गई थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : नवम्बर, 1992 में मंत्रिमण्डल की नियुक्ति समिति के समक्ष, आंध्रा बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री ए० टी० अकोलकर की यथापेक्षित आवश्यक सतर्कता संबंधी अनापत्ति प्राप्त करने और पद के लिए उनकी उपयुक्तता को ध्यान में रखने के पश्चात आन्ध्रा बैंक में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्ति करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था ।

Unemployment Insurance Scheme

3505. SMT. KAMLA SINHA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government are contemplating to give rise to an Unemployment Insurance Scheme in the industrial sector; and

(b) if so, what are the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED) : (a) and (b) Yes, Sir. A Committee has been set up in the Department of Industrial Development to examine the feasibility and operational details of the proposed Insurance Fund for Employees' (IFE) under National Renewal Fund. One of the objectives of the IFE is to explore the possibility of devising an Unemployment Insurance Scheme. The deiatls of the scheme will be known only after the submission of the Committee's Report.

Irregularities in Jaipur Division of LIC

3506. SHRI CHATURANAN MISHRA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the irregularities in Jaipur Division of LIC.

(b) whether LIC's internal audits reports have pointed out that 40 percent of the New business done in 1991-92 was bogus;

(c) whether it is a fact that a large number of policies of the Division lapsed within one year of 1991-92; and

(d) if so, what action has been taken to check such irregularities ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED) : (a) Yes, Sir.

(b) The total business done by Jaipur Division for the year 1991-92 was Rs. 522 crores. The aduit report has pointed out a difference of Rs. 31 crores in the completed New Business which was due to non-reduction of the figures in respect of cheques dishonoured.